भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1115

08 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

एएमपीएलआईएफआई 2.0

1115. डॉ. सुकान्त मजूमदार:

श्री विनोद कुमार सोनकर:

श्री भोला सिंह:

श्री राजा अमरेश्वर नाईक:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने एएमपीएलआईएफआई 2.0 (एसेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लेटफार्म फॉर लिवेबल, इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया) की पहल शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एएमपीएलआईएफआई 2.0 संपूर्ण देश के विभिन्न शहरी क्षेत्रो में उपलब्ध अपरिष्कृत आंकड़ों को एकत्र करने के उद्देश्य से एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करता है और यदि हां, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर साक्ष्य आधारित सूचना प्रदान करने के लिए एक व्यापक और सुलभ डाटाबेस उपलब्ध कराने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) से (घ): जी, सर। असेसमेंट एंड मोनिटरिंग फॉर लिवेब्ल, इंक्लूसिव एंड फ्यूचर-रेडी अर्बन इंडिया (एएमपीएलआईएफआई) 2.0 विभिन्न विषयों पर शहरों से डेटा संग्रह और एकत्रीकरण के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए, शहरी परिणाम फ्रेमवर्क 2022 के भाग के रूप में, 440+ मापदंडों के 14 क्षेत्रों पर 200 से अधिक शहरों से डेटा एकत्र किया गया है और सभी हितधारकों के लिए उपलब्ध कराया गया है। एएमपीएलआईएफआई 2.0 शहरी प्रशासकों को डेटा डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान करता है जिससे शहरों में साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सहायता मिलती है। यह उद्योग, स्टार्टअप,

शिक्षा जगत और अनुसंधान संस्थानों तक डेटा पहुंच को भी सक्षम बनाता है जिससे बाजार-संचालित समाधान के विकास और सहयोगात्मक कार्य को बढ़ावा मिलता है।

स्मार्ट सिटीज़ मिशन (एससीएम) द्वारा 2019 में डेटा स्मार्ट सिटीज़ रणनीति की शुरूआत भारत के शहरों में डेटा-संचालित शासन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस रणनीति ने 100 स्मार्ट शहरों में डेटा-संचालित नीतियों और कार्यान्वयन पर व्यापक कार्य को बढ़ावा देने में मदद की है।

एएमपीएलआईएफआई 2.0 के अलावा, मिशन ने विशिष्ट संस्थाओं के बीच संवेदनशील डेटा साझा करने के लिए एक नियंत्रित अभिगम, सुरक्षित तंत्र के रूप में इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज (आईयूडीएक्स) बनाया है। इससे देश के कई स्मार्ट शहरों में मोबिलिटी, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में नवीन समाधान तैयार करने में मदद मिली है। सभी मिशन शहर सक्रिय रूप से भारत सरकार के ओपन डेटा पोर्टल पर गैर-व्यक्तिगत डेटा साझा करते हैं।

कई स्मार्ट शहरों ने शहरों में डेटा को कैसे प्रबंधित और साझा किया जाना चाहिए और डेटा प्रशासन, सुरक्षा, सहयोग और नवाचार के आसपास तंत्र को परिभाषित करने के सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए सिटी डेटा परियोजनाएं तैयार की हैं। शहर अपनी सिटी डेटा नीतियों का उपयोग करके डेटा साझाकरण, मानकीकरण, गोपनीयता, सुरक्षा और स्वामित्व की रूपरेखा तय करने में सक्षम हैं।

मिशन ने एक साइबर सुरक्षा ढांचा तैयार किया है, जो साइबर सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर शहरों का मार्गदर्शन करता है। इसके अलावा, शहरों से सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित डेटा गोपनीयता और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। इस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण के कई चरण आयोजित किए गए हैं।

***